

## विचार बिन्दु

स्मृति पीछे दृष्टि डालती है और आशा आगे। -रामचंद्र टंडन

## राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की नैतिकता संकट में

राजस्थान में चिकित्सा तंत्र आज घोर संकट की तस्वीर पेश कर रहा है, और विशेषकर राजधानी जयपुर में इससे अनछूटा नहीं है। हाल के खुलासों, मीडिया रिपोर्टों और शोषों ने यह प्रमाणित किया है कि जहाँ चिकित्सा का मूल उद्देश्य रोगी की भलाई होना चाहिए, वहीं कहीं-कहीं इलाज का लक्ष्य लाभ बन गया है। बड़े निजी अस्पतालों में अनावश्यक भर्ती, जांच और ऑपरेशनों की बढ़ती प्रवृत्ति, बीमा घोटाले, दवा उद्योग तथा चिकित्सकों के बीच सांड-गाठ और अंग-तस्करी जैसी बीभत्स घटनाएँ रोगी-हित की हिफाजत करने वाली व्यवस्था की मौलिक कमजोरियों को उजागर करती हैं। राजस्थान के ग्रामीण व शहरी दोनों हिस्सों में यह संकट अलग-अलग रूपों में उभर रहा है और जयपुर, जहाँ चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र है, इन समस्याओं के सामने एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशनों की असामान्य रूप से ऊँची सुविचय जैसे हायटेरेक्टॉमी, सी-सेक्शन, हृदय सर्जरी और अर्थ्रोप्लास्टी केवल चिकित्सकीय प्रवृत्ति का मामला नहीं है; यह उस व्यवस्था का संकेत है जिसमें आर्थिक प्रोत्साहन चिकित्सकीय निर्णयों में घुस आते हैं। जयपुर जैसे महानगरों में उच्च-प्रोफाइल निजी संस्थान और कुछ वरिष्ठ चिकित्सक जिनकी पारिश्रमिक कई गुना होती है, का प्रभाव निर्णय-प्रक्रिया पर दिखाई देता है। राजधानी के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और उन्नत सुविधाएँ ग्रामीण मरीजों को आकर्षित करती हैं, पर साथ ही अनावश्यक प्रक्रियाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है-क्योंकि दूर-दराज के लोग मामूली बीमारी के लिए बड़े शहर आकर विशेषज्ञों पर निर्भर हो जाते हैं और अक्सर उनके पास विकल्पों की कमी रहती है।

बीमा प्रणाली, जो प्रमुखतः आर्थिक सुरक्षा और चिकित्सा तक पहुँच का जरिया है, कई मामलों में भरोसे के संकट में बदल चुकी है। जयपुर के कुछ केंसों में क्लेम अस्वीकार किए जाने, प्रक्रियागत बाधाओं और विवादित बिलिंग के आरोप सामने आए हैं, जिनसे लोगों का विश्वास मंजला हुआ है। कोविड-19 के समय में देशव्यापी जैसे कुछ आरत्यों ने यह दिखाया कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी पारदर्शिता लचीली हो सकती है। राजधानी के आस-पास के जिलों से आई शिकायतें इस बात का संकेत हैं कि बीमा और निजी अस्पताल के बीच के व्यवहार ने विशेषकर मध्यम आय वर्ग और गरीब रोगियों की वचत पर चोट की है।

लैब व डायग्नोस्टिक रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर उठते सवाल और कुछ पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के खतरनाक खेल ने चिकित्सा विज्ञान के आधार को भी हिला दिया है। जयपुर में किए गए कुछ छापे और जांचें इस ओर इशारा करती हैं कि नकदी लेनदेन और अनियमित रिपोर्टिंग जैसी प्रथाएँ मौजूद रही हैं। जब परीक्षण ही संदिग्ध हों तो निदान और उपचार दोनों प्रभावित होते हैं। छोटे शहरों व गांवों के मरीज जो जयपुर की लैबों पर भरोसा कर रिपोर्ट बनाते हैं, वे गलत रिपोर्ट के कारण अनावश्यक दवाइयों और अतिरिक्त प्रक्रियाओं के शिकार बन सकते हैं।

फार्मा उद्योग और चिकित्सकीय पेशे के बीच हितों का टकराव भी गंभीर रूप ले चुका है। ब्रांडेड दवाओं के प्रचार और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियों के बहाने चिकित्सकीय निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। जयपुर की कॉर्पोरेट क्लिनिक-हब संस्कृति में, जहां दवा कंपनियों की गतिविधियाँ ज्यादा दिखाई देती हैं, मरीजों को महँगी दवाएँ दी जाने के आरोप उभरते रहे हैं जबकि जेनरिक विकल्प उपलब्ध और प्रभाव्य होता है। अस्पतालों का दवा और उपकरण पर मार्जिन तथा बिलिंग में पारदर्शिता का अभाव राजधानी के मध्यम और निम्न आय वर्ग परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।

सबसे अंधावह पक्ष अंग-तस्करी और मानव शोषण के मामले हैं। राजस्थान के सीमांत इलाकों से जुड़े कुछ नेटवर्क ने कभी-कभी जयपुर के अस्पतालों व क्लिनिकों को भी अपने कामकाज के लिए उपयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महानगर का चिकित्सा-इकोसिस्टम पसरायी नेटवर्क के संपर्क में आ सकता है। नैकी या इलाज के नाम पर बहलाकर लाने, फर्जी भर्ती और परीक्षण करार कर अंगों के अवैध व्यापार में डालने जैसे क्रूर केवल कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता पर चोट है। ऐसे मामलों में अस्पतालों, चिकित्सकों और एजेंटों के आपसी नेटवर्क का होना चिंत्नीय है और पीछले परिवारों की सुरक्षा पर गहरा असर डालता है।

नियमों और नियामक संस्थाओं की कमजोरी इन कुप्रथाओं को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई कानूनी/डिजिटल रिपोर्टों को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई

**पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स का प्रमाण और नियमित निरीक्षण तेज करना होगा। केवल प्रमाणित लैबों को सरकारी या बीमा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, और अनियमितता पाई जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में नियमित आकस्मिक निरीक्षण, सैपल-ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय हैं।**

निजी मेडिकल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के त्वरित उदय ने मानकीकरण और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता को और बल दिया है। पारदर्शिता की कमी और नियमों का ढीलापन ही उन प्रथाओं को पोषित करता है जो चिकित्सा की मूल नैतिकता को चुनौती देती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुस्तरीय और तालमेल सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, चिकित्सा और अस्पतालों के वित्तीय व्यवहार पर पारदर्शिता अनिवार्य की जानी चाहिए। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को सार्वभौमिक व ऑडिट करने योग्य बनाना चाहिए ताकि हर जांच, इलाज और सर्जरी का रिकॉर्ड टिकाऊ और सार्वजनिक ऑडिट के लिए उपलब्ध रहे। जयपुर में डिजिटल इंटीग्रेशन मॉडल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है राज्य सरकार और लोक स्वास्थ्य विभागों को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए। इससे फर्जी रिपोर्ट, बिना सहमति के सर्जरी और नकली क्लेम की पहचान में मदद मिलेगी।

क्लिनिकल निर्णयों पर बाहरी निगरानी और नियमित क्लिनिकल ऑडिट लागू किया जाना चाहिए। जयपुर जैसे बड़े शहरों में उच्च-जोखिम वाले ऑपरेशनों के लिए स्वतंत्र चिकित्सकीय समितियों से पूर्व अनुमति जैसी प्रक्रियाएँ लागू कर के अनावश्यक सर्जरी घटाई जा सकती है। रेफरल और अन्य आर्थिक प्रोत्साहनों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और इस तरह के भुगतान के खुलासे पर सख्त सीमाएँ लगनी चाहिए।

पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स का प्रमाण और नियमित निरीक्षण तेज करना होगा। केवल प्रमाणित लैबों को सरकारी या बीमा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, और अनियमितता पाई जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में नियमित आकस्मिक निरीक्षण, सैपल-ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय हैं।

फार्मा कंपनियों और चिकित्सा पेशे के बीच हित-टकराव पर कड़ा नियंत्रण लागू होना चाहिए। चिकित्सकों को जेनरिक दवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाए और प्रलोभन स्वीकारने वालों पर सख्त दंडात्मक प्रवधान हों। मेडिकल शिक्षा में नैतिकता और पारदर्शिता की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पेशेवर ईमानदारी को प्राथमिकता दें। जयपुर के मेडिकल कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान इस पाठ्यक्रम को मॉडल बनाकर पूरे राज्य में प्रसारित कर सकते हैं।

अंग-तस्करी व मानव शोषण के मामलों के लिए त्वरित और विशेष जांच-प्रक्रियाएँ जरूरी हैं। पुलिस-स्वास्थ्य विभाग समन्वय को मजबूत किया जाए और पीडितों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील हेल्पलाइन व संरक्षण-प्रणालियाँ लागू की जाएँ। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व पंजीकृत करना होगा ताकि रोजगार के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगे। जयपुर में समर्पित कैपेन और जागरूकता कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रभाव्य साबित हो सकते हैं, विशेषकर जब स्थानीय सामाजिक संस्थाएँ और पंचायतें साथ दें।

मरीजों की जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है। मरीजों को इलाज के विकल्प, अनुमानित लागत, संभावित जोखिम और वैकल्पिक उपचारों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रभावी नागरिक शिकायत निवारण पैनाल जिनमें विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हों, तेज और निष्पक्ष निर्णय दें। स्वतंत्र मीडिया व जनजागरूकता अभियानों की भूमिका को बढ़ावा देना होगा क्योंकि खबरों और सार्वजनिक खुलासों ने कई कुख्यात प्रकरणों को उजागर किया है। जयपुर के स्थानीय मीडिया और नागरिक मंच इस दिशा में सक्रिय रहकर राज्यव्यापी प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

राजस्थान में चिकित्सा तंत्र की गरिमा और समाज का विश्वास तभी बहाल होगा जब नीति-निर्माण, कड़ा नियमन, तकनीकी पारदर्शिता और नैतिकता पर एक साथ जोर दिया जाए। अस्पताल और डॉक्टर सिर्फ बीमारी का उपचारक नहीं, समाज के भरोसे के रखवाले भी हैं। जब तक यह भरोसा लौटकर नहीं आता, तब तक स्वास्थ्य तंत्र में व्यापक रूप से जोखिम बना रहेगा और मरीजों, परिवारों तथा समाज को अज्ञान, चिंता और निष्पक्ष निर्णय दें। स्वतंत्र मीडिया व जनजागरूकता अभियानों की भूमिका को बढ़ावा देना होगा क्योंकि खबरों और सार्वजनिक खुलासों ने कई कुख्यात प्रकरणों को उजागर किया है। जयपुर के स्थानीय मीडिया और नागरिक मंच इस दिशा में सक्रिय रहकर राज्यव्यापी प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

-अतिथि संपादक,  
अविनाश जोशी,

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार

## बेटा 27 का, बेरोजगार... लड़की वाले मना कर गए!

कक्षा 10 के बाद कलम के साथ कारीगरी, तभी बसेगा घर



मदन सिंह काला

55 लाख सरकारी कुर्सियाँ खाली हैं। 65 करोड़ युवा भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। 27 साल का बेटा। घर में तनाव। लड़की वाले आए, चाय-नास्ता करते हुए पूछ लिया 'बेटा करते क्या हो?'। जबवा मिलना-“सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर”। बस रिश्ता यहीं खटाई में पड़ गया। ये कहानी हर गली-मोहल्ले की हो

3 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप की इथियोपिया-मोरक्को के भूभाग पर आधुनिक मानव-होमो सेपियंस-के रूप में विकसित हुआ। 2017 में नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार मोरक्को के जेबेल इरहूद में मिली 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी इसका प्रमाण है। उसका माथा ऊँचा था, टुडू उभरी हुई थी, दिमाग 1350 ग्राम का था। 65 हजार साल पहले उसका एक समूह अरब सागर के किनारे-किनारे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचा। गुजरात के तट से उतरकर वह पूरे भारत में फैल गया। आज भी 50 से 65 प्रतिशत भारतीयों का डीएनए एक है। मतलब हम सबके पूर्वज एक ही हैं। फिर जाति-धर्म की दीवार क्यों? ये दीवार 200 साल की मजबूरी थी, 1000 साल का विश्वास नहीं। आज हाथ में स्किल होगी तो जाति पूछने वाला शर्मिएगा। क्योंकि पेट जाति दिखाता है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई कानूनी/डिजिटल रिपोर्टों को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई

नियमों और नियामक संस्थाओं की कमजोरी इन कुप्रथाओं को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पाती। जयपुर में नई

उसी मानव ने अनाज उगाया, गाय पाली। अनाज ज्यादा हुआ तो 'बादर' चला - गेहूँ दो, दूध लो। हिसाब बराबर न हो तो झगड़ा हो, इसलिए 600 ईसा पूर्व तुर्क की लिडिया घाटी में पहला सिक्का बना। भारत में 5200 साल पहले मगध के राजा बिम्बिसार-अजातशत्रु के समय पंचमार्क सिक्के चले। इन्हें 'आहत सिक्के' कहते थे क्योंकि चाँदी की पत्ती काटकर हथौड़े से सूँट, बाल, हाथों के टम्पे लगाए जाते थे। ये राज के नाम के सिक्के नहीं थे, व्यापारी संघ और मगध-कोशल जैसी सरकारों ने ढाली। बाद में मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त-अशोक के समय ये सरकारी सिक्का बना। इसी सिक्के ने व्यापार को जन्म दिया, व्यापार से मण्डी बनी, मण्डी से भट्टी जलाई और उद्योग खड़े हुए। मानव ने हाथ से मशीन तक की यात्रा की। काम बदला तो समाज बदला, समाज बदला तो रिश्ते बदले। हमारा साल सी चूल्हे-चौके तक सीमित रही क्योंकि काम अलग थे। पुरुष खेत-जंगल, स्त्री घर-आँगन मिलते ही नहीं थे तो पहचान कैसे होती। इसलिए शादी माँ-बाप, पण्डित, कुण्डली तय करते थे। जाति देवी जाती थी, आचरण नहीं।

55 लाख खाली कुर्सियों का लेखा-जोखा

केन्द्र-राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-पंचायत में 1.8 करोड़ पद स्वीकृत हैं, पर 55 लाख कुर्सियाँ आज भी खाली पड़ी हैं। फिर भी सरकारी खजाने से 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इंसमें सेवारत 1.25 करोड़ कर्मचारी, 1 करोड़ पेशेवर और 1.25 करोड़ ठेका-संवित्ता-आँगनबाड़ी-आशा कार्यक्रमों जैसे अर्द्धसरकारी लोग शामिल हैं। यानी कुर्सियाँ 1.8 करोड़ की हैं, पर बोझ 3.5 करोड़ का। 50 प्रतिशत नहीं भर्ती अब ठेके-अनुबन्ध पर हो रही है,

फिर औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैण्ड की कपड़ा मिल हो या जपान की सिल्क फैक्ट्री, जब बोल-लड़की 8 घण्टे एक मशीन पर खुद हुए तो तीन बदलाव हुए। स्त्री के हाथ में तनख्वाह आई तो वह बोझ से सहारा बन गई। उसे 'फ्लॉ' की बेटों' की जगह "एना - मशीन ऑपरेटर" कहा जाने लगा। रोज 8 घण्टे साथ काम होगा तो लड़का-लड़की एक-दूसरे का गुस्सा, ईमानदारी, मेहनत देख लेंगे। कुण्डली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्मनी में आज 40 प्रतिशत शायियाँ ऑफिस-फैक्ट्री में होती हैं। वहीं कोई नहीं पूछता तुम कौन सी जाति हो, पूछते हैं "तुम प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करते हो?" यानी काम की जिम्मेदारी कैसे निभाती हो। मतलब साफ है - जब स्त्री-पुरुष साथ काम करेंगे तो जीवनसाथी का चुनाव कुण्डली से नहीं, आचरण से होगा। जाति और दहेज दोनों अपने आप खत्म हो जाएँगे।

-पाठक से सवाल: आपके घर का 18-25 साल का युवा क्या कर रहा है?

60 साल से अधिक उम्र के लोग जब विद्यार्थी थे तो माता-पिता के साथ खेत में हल चलते थे, दुकान पर सामान तोलते थे। सुबह स्कूल जाता थे, शाम को खेत-खलिहाय या दुकान पर हाथ बढाते थे। इसी शारीरिक श्रम से उनमें जिम्मेदारी, परिश्रम, समय की कद्र के संस्कार विकसित हुए। 10 साल की उम्र में हल को चारा डालना, 15 साल में बैल चलाना सीख गए थे। इसलिए वह पीढ़ी संघर्ष समझती है, पसीने की कीमत जानती है। आज का युवा कक्षा 10 पास कर निकलता है तो उसने जीवन में कभी एक ईंट नहीं लगाई, कभी 100 रुपये की बिक्की नहीं की। उसे स्किल सीखने का मौका ही नहीं मिला। हाथ से काम नहीं करा तो मेहनत की आदत कहीं से आएगी। इसलिए कक्षा 10 पास करने के बाद पढ़ाई के साथ जीवनव्ययन युक्त रोजगार देना देशहित में अति आवश्यक है।

यदि युवाओं को कक्षा 10 के बाद पढ़ाई के साथ रोजगार मिल जाए तो संविधान की प्रस्तावना के 'तीनों न्याय' में से आर्थिक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी संविधान प्रस्तावना कहती है - हम भारत के लोग, भारत की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जब 18 साल का युवा कक्षा 10 के बाद 20 हजार रुपये कमाने लगेगा तो वह आर्थिक न्याय की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। बिना रोजगार के प्रस्तावना का 'आर्थिक न्याय' कागज पर ही रह जाएगा।

यदि युवाओं को कक्षा 10 के बाद पढ़ाई के साथ रोजगार मिल जाए तो संविधान की प्रस्तावना के 'तीनों न्याय' में से आर्थिक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी संविधान प्रस्तावना कहती है - हम भारत के लोग, भारत की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जब 18 साल का युवा कक्षा 10 के बाद 20 हजार रुपये कमाने लगेगा तो वह आर्थिक न्याय की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। बिना रोजगार के प्रस्तावना का 'आर्थिक न्याय' कागज पर ही रह जाएगा।

55 लाख खाली कुर्सियों का लेखा-जोखा

केन्द्र-राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-पंचायत में 1.8 करोड़ पद स्वीकृत हैं, पर 55 लाख कुर्सियाँ आज भी खाली पड़ी हैं। फिर भी सरकारी खजाने से 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इंसमें सेवारत 1.25 करोड़ कर्मचारी, 1 करोड़ पेशेवर और 1.25 करोड़ ठेका-संवित्ता-आँगनबाड़ी-आशा कार्यक्रमों जैसे अर्द्धसरकारी लोग शामिल हैं। यानी कुर्सियाँ 1.8 करोड़ की हैं, पर बोझ 3.5 करोड़ का। 50 प्रतिशत नहीं भर्ती अब ठेके-अनुबन्ध पर हो रही है,

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

जर्मनी में कक्षा 10 के बाद 70 प्रतिशत बच्चे 'ड्युअल सिस्टम' में चले जाते हैं। सप्ताह में तीन दिन कम्पनी में मशीन चलाने हैं, दो दिन स्कूल जाते हैं। महीने के अन्त में एक लाख रुपये स्ट्राइपेण्ड लेते हैं। 18 साल का लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, पीछी यानी किराये का कमरा लेता है, बाइक लेता है। बेरोजगारी 3 प्रतिशत है। स्विट्जरलैण्ड में 60 प्रतिशत युवा 16 साल के बाद बैंक और फैक्ट्री में व्यावसायिक शिक्षा करते हैं। स्ट्राइपेण्ड सवा लाख रुपये महीना मिलता है। लड़की 20 साल की उम्र में बैंक में 90 हजार कमाती है इसलिए शादी समनता की होती है, समझौते की नहीं। जापान ने 15 साल के बच्चों को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम सिखाया। इन 25 से ज्यादा देशों का एक मन्त्र है - कक्षा 10 के बाद भटकना नहीं, स्किला जर्मनी का 18 साल का लड़का 1 लाख महीना कमाता है। भारत का 27 साल का लड़का 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलता है। शर्म किसे आनी चाहिए? एनसीआरबी का डेटा कहता है। 18 से 25 साल के युवाओं की कुल अपराध में भागीदारी 45 प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का युवा 16 से काम कर रहा है, भारत का युवा 18 से 25 तक 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलकर खाली बैठता है। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है। भारत की भरती में 4.17 अरब टन हाइड्रोकार्बन, 1.23 करोड़ टन लिथियम, पर तेल का सिर्फ 6-8 प्रतिशत निकल रहा है। हम कच्चा लोहा 40 रुपये किलो बेचकर चीन से स्टील 100 रुपये किलो खरीदते हैं। फर्क सिर्फ गलाने वाले हाथ का है। फैनट्रियाँ हैं पर 40 प्रतिशत पर खाली हैं क्योंकि 10वीं पास सीएनसी मशीन नहीं चला पाएँ। इम्पोर्टर को 10 सेल्समैन चाहिए, मैनुफैक्चर को 1000 मजदूर। हर साल 6 लाख करोड़ रुपये के हथियार बहार से मँगते हैं। एक लड़कू विमान 800 करोड़ का। अगर यही हाल हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में बने तो 20 हजार युवा को रोजगार मिले और वही पैसा आइएसआरओ में लगे। जापान ने 1945 के बाद हथियार नहीं बनाए, स्किल बनाई और आज कार बेचता है। हम स्किल नहीं दे रहे इसलिए आज भी खरीद रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 13.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार घाटा। मतलब हम दुनिया को कर्ज का कागज देते हैं, बदले में माल लेते हैं।

नतीजा सामने है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 15 से 35 साल के बीच 65 करोड़ युवा। हर साल 1.8 करोड़ बच्चे कक्षा 10 पास करके निकलते हैं। उनमें से 60 प्रतिशत न कॉलेज जा पाते हैं, न कोई हुनर सीख पाते हैं। 3 साल तक भटकते हैं। 18 साल की उम्र में न डिग्री, न स्किल, न तनख्वाह। छोटे किसान की औसत आय 10,218 रुपये महीना है। युवा खेती को मनरेगा वाला मजदूरी

परमाणु नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद 'Dual Work System' से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेंटिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पैशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

जर्मनी में कक्षा 10 के बाद 70 प्रतिशत बच्चे 'ड्युअल सिस्टम' में चले जाते हैं। सप्ताह में तीन दिन कम्पनी में मशीन चलाने हैं, दो दिन स्कूल जाते हैं। महीने के अन्त में एक लाख रुपये स्ट्राइपेण्ड लेते हैं। 18 साल का लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, पीछी यानी किराये का कमरा लेता है, बाइक लेता है। बेरोजगारी 3 प्रतिशत है। स्विट्जरलैण्ड में 60 प्रतिशत युवा 16 साल के बाद बैंक और फैक्ट्री में व्यावसायिक शिक्षा करते हैं। स्ट्राइपेण्ड सवा लाख रुपये महीना मिलता है। लड़की 20 साल की उम्र में बैंक में 90 हजार कमाती है इसलिए शादी समनता की होती है, समझौते की नहीं। जापान ने 15 साल के बच्चों को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम सिखाया। इन 25 से ज्यादा देशों का एक मन्त्र है - कक्षा 10 के बाद भटकना नहीं, स्किला जर्मनी का 18 साल का लड़का 1 लाख महीना कमाता है। भारत का 27 साल का लड़का 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलता है। शर्म किसे आनी चाहिए? एनसीआरबी का डेटा कहता है। 18 से 25 साल के युवाओं की कुल अपराध में भागीदारी 45 प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का युवा 16 से काम कर रहा है, भारत का युवा 18 से 25 तक 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलकर खाली बैठता है। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है। भारत की भरती में 4.17 अरब टन हाइड्रोकार्बन, 1.23 करोड़ टन लिथियम, पर तेल का सिर्फ 6-8 प्रतिशत निकल रहा है। हम कच्चा लोहा 40 रुपये किलो बेचकर चीन से स्टील 100 रुपये किलो खरीदते हैं। फर्क सिर्फ गलाने वाले हाथ का है। फैनट्रियाँ हैं पर 40 प्रतिशत पर खाली हैं क्योंकि 10वीं पास सीएनसी मशीन नहीं चला पाएँ। इम्पोर्टर को 10 सेल्समैन चाहिए, मैनुफैक्चर को 1000 मजदूर। हर साल 6 लाख करोड़ रुपये के हथियार बहार से मँगते हैं। एक लड़कू विमान 800 करोड़ का। अगर यही हाल हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में बने तो 20 हजार युवा को रोजगार मिले और वही पैसा आइएसआरओ में लगे। जापान ने 1945 के बाद हथियार नहीं बनाए, स्किल बनाई और आज कार बेचता है। हम स्किल नहीं दे रहे इसलिए आज भी खरीद रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 13.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार घाटा। मतलब हम दुनिया को कर्ज का कागज देते हैं, बदले में माल लेते हैं।

नतीजा सामने है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 15 से 35 साल के बीच 65 करोड़ युवा। हर साल 1.8 करोड़ बच्चे कक्षा 10 पास करके निकलते हैं। उनमें से 60 प्रतिशत न कॉलेज जा पाते हैं, न कोई हुनर सीख पाते हैं। 3 साल तक भटकते हैं। 18 साल की उम्र में न डिग्री, न स्किल, न तनख्वाह। छोटे किसान की औसत आय 10,218 रुपये महीना है। युवा खेती को मनरेगा वाला मजदूरी

समझता है। उसे पता नहीं कौशाब्बी का किसान ग्रीनहाउस टमाटर से 35 लाख सालाना कमा रहा है। फर्क स्किल का है। युवा 10 साल सरकारी नौकरी का इन्तजार करता है और 18 की उम्र 28 हो जाती है। लड़की वाले ओवरएज कहकर मना कर देते हैं। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है इसलिए 18 से 25 साल के युवाओं का अपराध 45 प्रतिशत है। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है सम्मान से जीने का अधिकार, अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। पर बिना रोजगार के न इज्जत है, न रोटी, न रिश्ता। 50 करोड़ युवा रोज 2.5-3 घण्टे रॉस्टर देखते हैं। 1 साल में 1000 घण्टे बर्बाद। उसी 1000 घण्टे में कोई लड़का, कॉलेज, ड्राम पायलट बन जाता। लघु वीडियो बुरे नहीं हैं। स्विट्जरलैण्ड का युवा दिन में 8 घण्टे स्विस् घड़ी बनाता है और रात में 30 मिनट देखता है। हमारा युवा दिन में 8 घण्टे रॉस्टर देखता है और रात में 30 मिनट नौकरी की टेन्शन लेता है। लघु वीडियो बनाने वाला 2 साल बाद बेरोजगार क्रिएटर कहलाता है, सीएनसी चलाने वाला 2 साल बाद रिस्क टेक्नियन कहलाता है। शादी के मण्डप में कौन बैठेगा आप खुद सोचिए। मोबाइल युवा का दुश्मन नहीं, शिक्षा का दुश्मन है। मोबाइल से लघु वीडियो बनाओ पर लघु वीडियो के लिए मोबाइल मत बनी। हाथ में स्किल होगी तो लघु वीडियो तुम्हें दूँगे, तुम लघु वीडियो को नहीं।

पर उम्मीद अभी बाकी है क्योंकि दुनिया के महान लोगों ने भी यही रास्ता अपनाया था। महात्मा गांधी लन्दन में बैरिस्टर पढ़ते समय खुद झाड़ू लगाते, जूते पॉलिश करते थे। दोस्त हैंसे थे 'मोहन, तू बैरिस्टर बनेगा या मोची?' गांधी कहते - "जो हाथ कलम पकड़ेगा, वह हाथ झाड़ू भी पकड़ेगा। श्रम की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है।" डॉ. कलाम 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे। रतन टाटा कर्नल से पहलक लौटे तो 6 महीने जमशेदपुर की भट्टी के पास लोहा गलवाया। धीरूभाई अम्बानी 14 साल की उम्र में यमन में पेट्रोल पम्प पर अटेंडण्ट थे। बरक ओबामा गर्मियों में आइसक्रीम बेचते थे। स्टीव जॉब्स अटारी में रत की शिफ्ट में गेम के अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये प्रयास अर्थव्यवस्था बनाया है।

कबीर का मानव शक्ति के उपयोग के लिए आख्यान आलसी पीढ़ी और सरकार दोनों के लिए है - "काल करे सो आज कर, आज करे सो अंब। पल में बल्य होयगी, बहुरी करोगे कबा" - यानी कल नहीं, आज नहीं - अभी। 18 साल का लड़का आईटीआई का फॉर्म निक भरेगा तो 27 साल 'तैयारी' में निकल जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये प्रयास अर्थव्यवस्था बनाया है।

जर्मनी में कक्षा 10 के बाद 70 प्रतिशत बच्चे 'ड्युअल सिस्टम' में चले जाते हैं। सप्ताह में तीन दिन कम्पनी में मशीन चलाने हैं, दो दिन स्कूल जाते हैं। महीने के अन्त में एक लाख रुपये स्ट्राइपेण्ड लेते हैं। 18 साल का लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, पीछी यानी किराये का कमरा लेता है, बाइक लेता है। बेरोजगारी 3 प्रतिशत है। स्विट्जरलैण्ड में 60 प्रतिशत युवा 16 साल के बाद बैंक और फैक्ट्री में व्यावसायिक शिक्षा करते हैं। स्ट्राइपेण्ड सवा लाख रुपये महीना मिलता है। लड़की 20 साल की उम्र में बैंक में 90 हजार कमाती है इसलिए शादी समनता की होती है, समझौते की नहीं। जापान ने 15 साल के बच्चों को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम सिखाया। इन 25 से ज्यादा देशों का एक मन्त्र है - कक्षा 10 के बाद भटकना नहीं, स्किला जर्मनी का 18 साल का लड़का 1 लाख महीना कमाता है। भारत का 27 साल का लड़का 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलता है। शर्म किसे आनी चाहिए? एनसीआरबी का डेटा कहता है। 18 से 25 साल के युवाओं की कुल अपराध में भागीदारी 45 प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का युवा 16 से काम कर रहा है, भारत का युवा 18 से 25 तक 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलकर खाली बैठता है। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है। भारत की भरती में 4.17 अरब टन हाइड्रोकार्बन, 1.23 करोड़ टन लिथियम, पर तेल का सिर्फ 6-8 प्रतिशत निकल रहा है। हम कच्चा लोहा 40 रुपये किलो बेचकर चीन से स्टील 100 रुपये किलो खरीदते हैं। फर्क सिर्फ गलाने वाले हाथ का है। फैनट्रियाँ हैं पर 40 प्रतिशत पर खाली हैं क्योंकि 10वीं पास सीएनसी मशीन नहीं चला पाएँ। इम्पोर्टर को 10 सेल्समैन चाहिए, मैनुफैक्चर को 1000 मजदूर। हर साल 6 लाख करोड़ रुपये के हथियार बहार से मँगते हैं। एक लड़कू विमान 800 करोड़ का। अगर यही हाल हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में बने तो 20 हजार युवा को रोजगार मिले और वही पैसा आइएसआरओ में लगे। जापान ने 1945 के बाद हथियार नहीं बनाए, स्किल बनाई और आज कार बेचता है। हम स्किल नहीं दे रहे इसलिए आज भी खरीद रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 13.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार घाटा। मतलब हम दुनिया को कर्ज का कागज देते हैं, बदले में माल लेते हैं।

कबीर का मानव शक्ति के उपयोग के लिए आख्यान आलसी पीढ़ी और सरकार दोनों के लिए है - "काल करे सो आज कर, आज करे सो अंब। पल में बल्य होयगी, बहुरी करोगे कबा" - यानी कल नहीं, आज नहीं - अभी। 18 साल का लड़का आईटीआई का फॉर्म निक भरेगा तो 27 साल 'तैयारी' में निकल जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये प्रयास अर्थव्यवस्था बनाया है।